लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4941

01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

लघु वस्त्र इकाइयों को मजबूत करना

4941. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा लघु-स्तरीय कपड़ा इकाइयों, विशेषकर सांगली जैसे वस्त्र केन्द्रों में, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए उन्हें एकीकृत करने और मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) मित्रा योजना के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है और सांगली और अन्य प्रमुख वस्त्र क्षेत्रों में वस्त्र समूहों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र विनिर्माण में अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के लिए लक्षित पहल शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र में वस्त्र उद्योगों के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (घ): सरकार संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ एमएसएमई के समग्र विकास पर केंद्रित है और महाराष्ट्र सहित पूरे देश में कई योजनाएं लागू कर रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; मांग आधारित, रोजगार उन्मुख, कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा क्षेत्र को एंड-टू-एंड सहायता देने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम शामिल हैं। वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना भी क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के तहत विपणन, कौशल विकास, कलस्टर विकास, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा विकसित करने के उद्देश्य से, सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2027-28 तक की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपये की योजना के साथ ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड साइटों पर 7 (सात) पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। सरकार ने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने हेतु 7 साइटों अर्थात तमिलनाडु (विरुद्धनगर), तेलंगाना (वारंगल), गुजरात (नवसारी), कर्नाटक (कलबुर्गी), मध्य प्रदेश (धार), उत्तर प्रदेश (लखनऊ) और महाराष्ट्र (अमरावती) को अंतिम रूप दिया है।

इस योजना में कुल परियोजना लागत का 30% विकास पूंजी समर्थन (डीसीएस) शामिल है, जो ग्रीनफील्ड पार्क के लिए 500 करोड़ रुपये तक और ब्राउनफील्ड पार्क के लिए 200 करोड़ रुपये तक है, जो योजना दिशानिर्देशों के अधीन है। इस योजना में पार्क में जल्दी से जल्दी विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रति पार्क 300 करोड़ रुपये तक की प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस) की भी परिकल्पना की गई है। यह प्रोत्साहन विस्तृत योजना दिशानिर्देशों में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन है।

देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1480 करोड़ रुपये के परिव्यय से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) शुरू किया गया, जो 31.03.2026 तक वैध है। मिशन का उद्देश्य अनुसंधान एवं नवाचार तथा मशीनरी एवं विशेष फाइबर के स्वदेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना, उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना, भारत के निर्यात को बढ़ाना तथा तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में अपेक्षित कौशल वाले मानव संसाधन तैयार करना है।

इसके अलावा, बेंचमार्क टेक्सटाइल मशीनरी में योग्य निवेश के लिए एकमुश्त पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान करके वस्त्र क्षेत्र के प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के तहत, महाराष्ट्र राज्य में 1,394 लाभार्थियों को कुल 309.2 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

***